एम.एम. से पहले कुमार, जे

गुरचरण सिंह और अन्य,-याचिकाकर्ता बनाम

गुरुद्वारा श्री सिंह सभा (रजि.),-प्रतिवादी सी.आर. नं. 2004 का 1124

4 मार्च, 2004

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-0.21 रूल 32, 0.21 आर1.35- भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 227-सिविल न्यायालय अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए डिक्री पारित करते हुए लाइसेंसधारियों को निधन हो चुके स्थान को खाली करने का निर्देश देता है।

परिसर - डिक्री धारक डिक्री के निष्पादन की मांग कर रहा है - निष्पादन न्यायालय कब्जे के वारंट जारी कर रहा है - उसे चुनौती - 0.21 रूल1.35 सीपीसी प्रदान करता है कि कब्जे की डिलीवरी का निर्देश देने वाले डिक्री के मामलों में कब्जे के वारंट जारी किए जा सकते हैं - सिविल कोर्ट केवल निधन के आदेश को खाली करने का निर्देश देता है परिसर और सौंपने का आदेश नहीं दे रहे हैं

कब्ज़ा - व्याख्या - क्या कब्जे के वारंट जारी करने वाले निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध है - माना जाता है, नहीं - 0.21 आर 1.32 (5) सीपीसी के तहत, न्यायालय यह निर्देश देने में सक्षम है कि किया जाने वाला कार्य जहां तक संभव हो किया जा सकता है। या तो खुद डी.एच. द्वारा या जे.डी. की कीमत पर न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा - न्यायालय द्वारा परिसर खाली करने के निर्देश का मतलब कब्जा सौंपने का निर्देश देना है और कुछ नहीं - तकनीकी आपत्तियां उठाकर डिक्री को विफल नहीं किया जा सकता है - आदेश निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित को बरकरार रखा गया।

यह माना गया कि डिक्री धारक की पीड़ा निष्पादन के चरण से शुरू होती है। निर्णय देनदारों द्वारा डिक्री धारकों को डिक्री के फल का आनंद लेने से वंचित करके डिक्री के निष्पादन को विफल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। निर्णय और डिक्री डिक्री धारक के पक्ष में पारित किया गया है - प्रतिवादी ने अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए अपने मुकदमे को डिक्री करके निर्णय देनदार को निर्देश दिया है - याचिकाकर्ताओं को दो कमरे खाली करने और रुपये की दर से हर्जाना देने का भी निर्देश दिया गया है। 1000 अपराह्न मुकदमा दायर करने की तारीख से लेकर कमरा खाली कराने तक। किसी लाइसेंसधारी के खिलाफ परिसर खाली करने के निर्देश की मांग करने वाला अनिवार्य निषेधाज्ञा का मुकदमा उन मामलों में चल सकता है, जहां लाइसेंस समाप्त कर

दिया गया है और कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस की समाप्ति के बाद सभी अधिकार, शीर्षक या हित खो देता है। सूट संपत्ति. ऐसा डिक्री 0.21 Rl.32 के तहत निष्पादन योग्य हैं।

इसके अलावा, न्यायालय यह निर्देश देने में पूरी तरह से सक्षम होगा कि जो कार्य किया जाना आवश्यक है वह डिक्री धारक द्वारा या तो स्वयं या निर्णय देनदार की कीमत पर न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए डिक्री के तत्काल निष्पादन में, जहां लाइसेंसधारी से कब्ज़ा मांगा जाता है। उक्त आदेश कानून की भावना और विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार जोड़े गए स्पष्टीकरण के अनुरूप है। गुरुद्वारा साहिब में स्थित परिसर को खाली करने का निर्देश, जहां जे.डी. याचिकाकर्ताओं को सेवादार होने के नाते रहने की अनुमति दी गई थी, कब्जा सौंपने का निर्देश देने का एक और रूप और तरीका है। ट्वीडलेडी ट्वीडलम है। इसका मतलब कब्ज़ा सौंपने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है और इसलिए, विधि आयोग द्वारा सुझाए गए व्यापक दृष्टिकोण का पालन किया जाना चाहिए क्योंकि यह न्याय के उद्देश्य को पूरा करता है। तकनीकी आपत्तियां उठाकर शासनादेश को विफल नहीं किया जा सकता।

याचिकाकर्ताओं के वकील अमन बाहरी।

बी.एस. गुगलियानी, कैविएटर के वकील।

निर्णय

एम.एम. कुमार, जे.

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 (संक्षिप्तता के लिए 'संहिता') के तहत दायर यह याचिका सिविल जज द्वारा पारित 23 फरवरी, 2004 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना करती है। जूनियर डिवीजन), चंडीगढ़ में 13 अगस्त, 2003 के निष्पादन आवेदन संख्या 98 में। निष्पादन न्यायालय ने निर्देश दिया है कि अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए डिक्री को निष्पादित करने के लिए जहां ध्वस्त परिसर को खाली करने का निर्देश जारी किया गया है, कब्जे का वारंट जारी किया जाए। उचित पाठ्यक्रम होगा. सिविल

जज (जूनियर डिवीजन), चंडीगढ़ द्वारा पारित 4 अगस्त, 2003 की डिक्री को डीएच-प्रतिवादी द्वारा निष्पादित करने की मांग की गई है।

(2) यह उल्लेख करना उचित है कि प्रतिवादी-प्रतिवादी ने अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए 16 अगस्त, 2003 को सिविल सूट नंबर 243 दायर किया, जिसमें उत्तरदाताओं (यहां जेडी-याचिकाकर्ता) को कमरा नंबर 7 के खाली कब्जे को खाली करने और सौंपने का निर्देश दिया गया था। दो कमरों का सेट) गुरुद्वारा से जुड़े सेराई में स्थित है और रुपये की वसूली के लिए। 15 जून, 1999 से 15 अगस्त, 2000 तक प्रभावी क्षति के रूप में 84,200 रु. कमरा नंबर 7 के अनधिकृत उपयोग और कब्जे के लिए और भविष्य में होने वाले नुकसान के लिए 6000 रुपये प्रति माह। मुकदमा दायर करने की तारीख से अंतिम वसूली तक 6000 प्रति माह।

(3) जेडी-याचिकाकर्ता लाइसेंसधारी थे और उन्हें डीएच-प्रतिवादी द्वारा प्रदान किए गए आवास में रहने की अनुमति दी गई थी क्योंकि वे सेवादार के रूप में काम कर रहे थे। बाद में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं और टू रूम सेट में रहने का लाइसेंस भी ख़त्म हो गया था. जेडी-याचिकाकर्ताओं ने स्वीकार किया है कि उन्होंने अपनी समाप्ति के खिलाफ मुकदमा दायर किया है जिसे खारिज कर दिया गया है। उन्होंने विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की है जो लंबित है लेकिन कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया है। डीएच-प्रतिवादी द्वारा दायर मुकदमे का फैसला सुनाया गया है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) चंडीगढ़ द्वारा 4 अगस्त, 2003 को पारित डिक्री, जिसे निष्पादित करने की मांग की गई है, इस प्रकार है:

'यह आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादियों को आदेश की तारीख से दो महीने के भीतर गुरुद्वारा में स्थित दो कमरे खाली करने का निर्देश दिया जाता है। उन्हें रुपये की दर से हर्जाना देने का भी निर्देश दिया गया है। मुकदमा दायर करने की तारीख से कमरे खाली करने तक 1000 प्रति माह।"

(4) जब उपरोक्त उल्लिखित डिक्री को डिक्री-धारक-प्रतिवादी द्वारा निष्पादित करने की मांग की गई थी, तो निर्णय-देनदार-याचिकाकर्ता द्वारा आपत्ति उठाई गई थी कि आदेश के तहत अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए डिक्री के निष्पादन के लिए कब्जे का कोई वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। 21 नियम 32. सिविल जज ने पक्षों के वकीलों और विभिन्न पक्षों के वकीलों द्वारा दी गई विस्तृत दलीलों पर विचार करने के बाद

निर्णयों में निम्नलिखित क्रम दर्ज किया गया:-

यह एक स्थापित कानून है कि किसी लाइसेंसधारी के मामले में यदि इसे समाप्त कर दिया जाता है तो अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा कायम रखा जा सकता है और कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं है। लाइसेंस की समाप्ति के बाद लाइसेंसधारी, मुकदमे की संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अधिकार या शीर्षक या हित खो देता है और अनिवार्य निषेधाज्ञा के डिक्री के निष्पादन के मामले में, जेडी को सिविल कारावास या कुर्की के लिए भेजने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए डिक्री के निष्पादन का एकमात्र उद्देश्य संपत्ति के रूप में जेडी को एक कार्य करने के लिए मजबूर करना है जिसे करने के लिए अदालत ने निर्देश दिया है और अदालत को पर्याप्त शक्ति प्राप्त है। उप नियम 5 के तहत जेडी को कब्ज़ा सौंपने के लिए दिए जाने वाले निर्देशों के अलावा या उसके बदले में एक आदेश पारित करने के लिए।

13. इसके अलावा, कब्जे के वारंट पहले जारी किए गए थे और एकपक्षीय स्थगन दिया गया था और उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई है। स्टे को हटाने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था और, दिनांक 27 जनवरी, 2004 के आदेश के तहत श्री जे.एस. की अदालत द्वारा स्टे को हटा दिया गया है। क्लार, एल.डी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ और आज तक, जेडी ने किसी भी अदालत से कोई स्थगन आदेश पेश नहीं किया है।

14. इसलिए यदि कब्जे के वारंट जारी किए जाते हैं तो उन्हें आगे की न्यायिक जांच के लिए रखा जा सकता है और यदि वे गलत पाए जाते हैं, तो निष्पादन पर रोक लगाई जा सकती है और जेडी को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर जेडी डालते हैं नागरिक कारावास के माध्यम से सलाखों के पीछे, अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए डिक्री में जहां कब्ज़ा मांगा जाता है और यदि न्यायालय का आदेश अनुचित पाया जाता है, तो जेडी के प्रति पूर्वाग्रह होने वाला है। अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए डिक्री के निष्पादन में सबसे उपयुक्त आदेश जहां लाइसेंसधारी से कब्जा मांगा जाता है, कब्जे के वारंट जारी करना है। इसलिए, कब्जे के वारंट जारी न करने के लिए जेडी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है और एलडी का अनुरोध किया गया है। कब्जे के वारंट जारी करने के लिए डीएच को अनुमति दी गई है।"

निर्णय देनदार याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री अमित बाहरी ने तर्क दिया है कि निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश पेटेंट अवैधता से ग्रस्त है क्योंकि संहिता के आदेश 21 नियम 32 के तहत कब्जे का कोई वारंट जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि न्यायालय द्वारा पारित डिक्री ऐसा नहीं करती है। कब्ज़ा सौंपने पर विचार न करें. विद्वान वकील के अनुसार एक बार कब्ज़ा सौंपने के लिए मुकदमे में एक विशिष्ट प्रार्थना की गई है और यहां तक कि इस आशय का एक

मुद्दा भी तैयार किया गया है, तो यह उस प्रार्थना को अस्वीकार करने के समान होगा यदि डिक्री में कब्ज़ा सौंपने के लिए कोई विशेष निर्देश जारी नहीं किया गया है। . इसलिए डिक्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा जो अस्वीकार कर दिया गया है, उसे कार्यकारी न्यायालय द्वारा इम्पू द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है

उन्होंने यह तर्क देने के लिए संहिता के आदेश 21 नियम 35 का भी हवाला दिया है कि केवल कब्जे की डिलीवरी का निर्देश देने वाले डिक्री के मामलों में ही ऐसा आदेश पारित किया जा सकता है और निष्पादन न्यायालय ने कब्जे का वारंट जारी करके अवैधता की है। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने सरूप सिंह बनाम दर्योधन सिंह (1) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले और पृथ्वी सिंह और अन्य बनाम नाथा के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है। राम और दूसरा (2).

(6) श्री बी.एस. डिक्री-धारक-कैविएटर के विद्वान वकील गुगलियानी ने तर्क दिया है कि ऐसे मामलों में जहां परिसर को खाली करने के लिए अनिवार्य निर्देश जारी किए गए हैं, सिवाय इसके कि कब्जा सौंपना होगा, ऐसी डिक्री पर कोई अन्य व्याख्या नहीं की जा सकती है। विद्वान वकील के अनुसार जिन कमरों को खाली करने का निर्देश दिया गया है, वे गुरुद्वारा साहिब में स्थित हैं, जो जजमेंट देनदार-याचिकाकर्ताओं को तब दिए गए थे जब वे गुरुद्वारे के सेवादार के रूप में काम कर रहे थे। वर्ष 1999 में उनकी सेवाएँ समाप्त होने के बाद उन्हें उन कमरों में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और डिक्री धारक-प्रतिवादी द्वारा दायर मुकदमे में उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया है और निर्णयकर्ता देनदार-याचिकाकर्ता को उन कमरों को खाली करने का निर्देश दिया गया है। आगे यह निर्देश दिया गया है कि निर्णय देनदार-याचिकाकर्ताओं को रुपये की दर से हर्जाना देना होगा। 1000 अपराह्न मुकदमा दायर करने की तारीख से उसके ख़ाली होने तक। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने एमएसटी के रूप में रिपोर्ट किए गए फैसले पर भरोसा जताया है। हाजरा बनाम अब्दुल मजीद मट्टू और अन्य (3)।

7) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और सिविल जज द्वारा पारित 4 अगस्त, 2003 के फैसले और डिक्री और निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करने के बाद, मेरी सुविचारित राय है कि यह याचिका योग्यता से रहित है। यह सच ही कहा गया है कि डिक्री धारक की पीड़ा निष्पादन के चरण से ही शुरू हो जाती है। निर्णय-देनदारों द्वारा डिक्री धारकों को डिक्री के फल का आनंद लेने से वंचित करके डिक्री के निष्पादन को विफल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। वर्तमान मामले में, डिक्री-धारक-प्रतिवादी के पक्ष में अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए उनके

मुकदमे को डिक्री करके निर्णय और डिक्री पारित की गई है, जिसमें निर्णय-देनदार-याचिकाकर्ताओं को दो कमरे खाली करने और रुपये की दर से हर्जाना देने का निर्देश दिया गया है। 1000 अपराह्न मुकदमा दायर करने की तारीख से लेकर कमरा खाली कराने तक। किसी लाइसेंसधारी के खिलाफ परिसर खाली करने के निर्देश की मांग करने वाला अनिवार्य निषेधाज्ञा का मुकदमा उन मामलों में चल सकता है, जहां लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है और कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस की समाप्ति के बाद सभी अधिकार, शीर्षक या हित खो देता है। सूट संपत्ति. ऐसे आदेश आदेश 21 नियम 32 के तहत निष्पादन योग्य हैं, जो निम्नानुसार है: -

“आर.32. दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए या किसी निषेधाज्ञा के विशिष्ट पालन के लिए डिक्री (1) जहां वह पक्ष जिसके विरुद्ध किसी अनुबंध के विशिष्ट पालन के लिए, या दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए, या किसी निषेधाज्ञा के लिए डिक्री पारित की गई है। डिक्री का पालन करने का अवसर और जानबूझकर इसका पालन करने में विफल रहा है, तो उसकी संपत्ति की कुर्की द्वारा वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री के मामले में, या विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री के मामले में डिक्री को लागू किया जा सकता है। एक अनुबंध या निषेधाज्ञा के लिए सिविल जेल में उसकी हिरासत, या उसकी संपत्ति की कुर्की या दोनों द्वारा।

(2) जहां वह पक्ष जिसके विरुद्ध विशिष्ट निष्पादन या निषेधाज्ञा पारित की गई है, एक निगम है; डिक्री को निगम की संपत्ति की कुर्की द्वारा या, न्यायालय की अनुमति से, निदेशकों या उसके अन्य प्रमुख अधिकारियों की सिविल जेल में नजरबंदी द्वारा, या कुर्की और नजरबंदी दोनों द्वारा लागू किया जा सकता है।

(3) जहां उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के तहत कोई भी कुर्की छह महीने (या पी) के लिए लागू रहती है, यदि निर्णय-देनदार ने डिक्री का पालन नहीं किया है और डिक्री-धारक ने आवेदन किया है कुर्क की गई संपत्ति बेची गई, ऐसी संपत्ति बेची जा सकती है और प्राप्त आय में से न्यायालय डिक्री-धारक को ऐसा मुआवजा दे सकता है जो वह उचित समझे, और उसके आवेदन पर निर्णय-देनदार को शेष राशि (यदि कोई हो) का भुगतान करेगा (ए) ,

एपी, डी, एचपी, के. एमपी, एम, पीयू)।

(4) जहां निर्णय-देनदार ने डिक्री का पालन किया है और उसे निष्पादित करने की सभी लागतों का भुगतान किया है, जिसे वह भुगतान करने के लिए बाध्य है, या जहां, कुर्की की तारीख से छह महीने डी, एचपी, एमपी, पीयू के अंत में, एपी, के, एम ने बेची गई संपत्ति के लिए कोई आवेदन नहीं किया है, या यदि आवेदन देने से इनकार कर दिया गया है, तो कुर्की समाप्त हो जाएगी।

5) जहां किसी अनुबंध के विशिष्ट पालन के लिए या किसी निषेधाज्ञा के लिए डिक्री का पालन नहीं किया गया है, न्यायालय उपरोक्त सभी या किसी भी प्रक्रिया के बदले में या इसके अतिरिक्त, निर्देश दे सकता है कि जो कार्य किया जाना आवश्यक है वह किया जा सकता है। डिक्री-धारक या न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्णय-देनदार की कीमत पर, जहां तक संभव हो, किया जाता है, और कार्य किए जाने पर किए गए खर्चों को ऐसे तरीके से सुनिश्चित किया जा सकता है जैसा कि न्यायालय निर्देशित कर सकता है और कर सकता है ऐसे वसूल किया जाए जैसे कि उन्हें डिक्री में शामिल किया गया हो।

स्पष्टीकरण - संदेह को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि जिस कार्य को करने की आवश्यकता है उसकी अभिव्यक्ति में निषेधात्मक और साथ ही अनिवार्य निषेधाज्ञा शामिल है।

(8) नियम 32 के उप-नियम (1) और (2) के अवलोकन से पता चलता है कि उल्लंघन के मामले में, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायालय द्वारा जारी निषेधाज्ञा, सिविल जेल में हिरासत में रखने या संपत्ति की कुर्की के संबंध में प्रावधान है। या दोनों को लागू किया जा सकता है। उप-नियम (3) वह अवधि प्रदान करता है जिसके लिए कुर्की आदेश लागू रह सकता है और उसके बाद संलग्न संपत्ति बेची जा सकती है। संपत्ति बेचने के बाद, न्यायालय डिक्री-धारक को मुआवजा दे सकता है जैसा वह उचित समझे।

(9) 1 जुलाई, 2002 से संशोधन द्वारा उप-नियम (5) में जोड़े गए स्पष्टीकरण की सिफारिश विधि आयोग ने अपनी 154वीं रिपोर्ट में की थी क्योंकि इसमें प्रयुक्त किए जाने वाले आवश्यक अभिव्यक्ति अधिनियम के संबंध में विचारों का टकराव था। उपनियम (5). विधि आयोग की टिप्पणी का उल्लेख करना उचित होगा, जिसके कारण संशोधन की ओर प्रश्न उठाया गया:-

“8.1.1. सिविल प्रक्रिया संहिता में न्यायालय द्वारा जारी निषेधाज्ञा की अवज्ञा पर दंडित करने का प्रावधान है। संहिता का आदेश 21, नियम 32 इस विषय से संबंधित है। ऐसी अवज्ञा के लिए निर्णय-देनदार की गिरफ्तारी या उसकी संपत्ति की कुर्की के अलावा, आदेश 21, नियम 32, उप-नियम (5) में यह प्रावधान है कि जहां किसी अनुबंध के विशिष्ट पालन के लिए डिक्री या निषेधाज्ञा का पालन नहीं किया गया है। न्यायालय, ऊपर उल्लिखित अन्य प्रक्रियाओं के बदले में या इसके अतिरिक्त, निर्देश दे सकता है कि "किया जाने वाला कार्य", जहां तक संभव हो, डिक्री-धारक या न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। निर्णय-देनदार की लागत. कार्य किए जाने पर, इसे करने में किए गए खर्चों का पता उस तरीके से लगाया जा सकता है जैसा न्यायालय निर्देशित करे और इसे ऐसे वसूल किया जा सकता है जैसे कि ये खर्च डिक्री में शामिल किए गए हों।

8.1.2. विचारार्थ प्रश्न.–अब संहिता के आदेश 21, नियम 32(5) में "अपेक्षित कार्य" शब्द के अर्थ को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। क्या ये शब्द उस स्थिति को भी कवर करते हैं जहां डिक्री में निषेधात्मक निषेधाज्ञा शामिल की गई है या, क्या वे उन मामलों तक ही सीमित हैं जहां डिक्री अनिवार्य है?

(10) विधि आयोग ने भी इस विषय पर दो परस्पर विरोधी विचारों को देखा और उन्हें व्यापक दृष्टिकोण और संकीर्ण दृष्टिकोण कहा। व्यापक दृष्टिकोण, जिसे संशोधन के लिए अपनाया गया था, को एक निश्चित मार्ग में बाधा उत्पन्न करने से निर्णय-देनदार को इलाहाबाद के फैसले द्वारा दर्शाया गया है। जब निर्णय-देनदार ने बाधाएँ उत्पन्न करना शुरू कर दिया, तो डिक्री-धारक ने प्रार्थना करते हुए निष्पादन आवेदन दायर किया: -

(ए) आपत्तिजनक निर्माणों की कुर्की: (बी) उन निर्माणों को हटाना:

(सी) सिविल जेल में निर्णय-देनदार की नजरबंदी।

(11) निर्णय-देनदार द्वारा एक आपत्ति उठाई गई थी कि आदेश 21 नियम 32(5) के प्रावधान द्वारा डिक्री के निष्पादन को उचित नहीं ठहराया गया था। हालाँकि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि यह स्वीकार्य था और निम्नानुसार कहा गया था: -

“16. आर.32 के विभिन्न खंड यानी 1, 2 और 3 अप्रत्यक्ष तरीके हैं जो निषेधाज्ञा के अनुपालन को लागू करने के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक आगे की कार्रवाई के लिए एक मध्यवर्ती कदम है। हालाँकि, इससे हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि निषेधात्मक निषेधाज्ञा के लिए डिक्री का निष्पादन यहीं समाप्त हो जाना चाहिए। जब निर्णय-देनदार डिक्री का घोर उल्लंघन करता है ताकि डिक्री को ही रद्द कर दिया जा सके तो निष्पादन इतना सीमित नहीं किया जा सकता है और डिक्री-धारक को एक नया मुकदमा दायर करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इस तरह की व्याख्या पर विचार नहीं किया जा सकता है और यह मामले पर बहुत अधिक तकनीकी और संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाएगी। कानून ने हमेशा कार्यवाहियों की बहुलता के प्रति अपनी नापसंदगी व्यक्त की है और एक ऐसी व्याख्या के पक्ष में झुक गया है जो कार्यवाहियों की बहुलता को रोक सकती है बजाय इसके कि जो इसे उत्पन्न करेगी।

17. वहां इस्तेमाल किए गए महत्वपूर्ण शब्द हैं, अदालत उपरोक्त सभी या किसी भी प्रक्रिया के बदले में या उसके अतिरिक्त, यानी संपत्ति की कुर्की या सिविल जेल में हिरासत में रख सकती है। यह अभिव्यक्ति उप-नियम (1) या (2) और उप-नियम (5) के तहत दिए गए तरीके से डिक्री

को निष्पादित करने के लिए अदालत के अधिकार के दायरे को बढ़ाती है, नियम अदालत को यह निर्देश देने का अधिकार देता है कि कार्य आवश्यक है किया जाना डिक्री-धारक आदि द्वारा जहां तक संभव हो किया जा सकता है। कुछ अदालतों ने जो व्याख्या की है वह यह है कि किया जाने वाला कार्य शब्द केवल डिक्री के तहत एक अनिवार्य कार्य को संदर्भित करता है।

यह संकीर्ण अर्थ, एमवी दृश्य में, उस अधिनियम के लिए इस शब्द को निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है जो उस अधिनियम से संबंधित है जिसके लिए विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री दी गई थी या किसी अन्य कार्य के लिए भी जिसका प्रदर्शन डिक्री को लागू करने के लिए आवश्यक है। ।" (महत्व जोड़ें)

(12) विधि आयोग ने भी विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों का हवाला देते हुए संकीर्ण दृष्टिकोण पर ध्यान दिया, जो इस प्रकार हैं

अंतर्गत

«

(i) आंध्र प्रदेश (एवुरु बेनकटा सुब्बैया बनाम)।सृष्टि वीरय्या (4).

(ii) कलकत्ता (हेम चंद्र बनाम नरेंद्र नाथ। (5)।

(iii) कर्नाटक (करियप्पा बनाम हल्दप्पा। (6) (भट जे)।

(iv) केरल (जोसेफ बनाम मक्कारू। (7) (एम.एस. मेनन और

बी. वेलु पिल्लई जे.जे.)।

(v) मद्रास (नारी चिन्नब्बा चेट्टी बनाम)

ई. चेंगलरोया चेट्टी.(8) और

(vi) पंजाब (मुरारी लाई बनाम नवल किशोर।(9)

(एस.एस. दुलत और डी.के. महाजन, जे.जे.)।

(13) सरूप सिंह के मामले (सुप्रा) में दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले का उल्लेख करते हुए, विधि आयोग ने निम्नानुसार कहा है: -

(4) (5) (6) (7) (8) (9)

“8.1.10. दिल्ली के एक मामले में (सरूप सिंह बनाम डायलिम सिंह, एआईआर 1972 डेल 142 (एफबी) तुलना आदेश 21, नियम 32 और आदेश 21 नियम 35 के बीच थी। लाइसेंसधारी के खिलाफ जारी निषेधाज्ञा कब्जे वाले परिसर को खाली करने के लिए थी।

यह माना गया कि लाइसेंसधारी को बेदखल करने के कदमों का मतलब, व्यावहारिक रूप से, लाइसेंसधारी (निर्णय-देनदार) को बेदखल करना होगा। आदेश 21 नियम 32 के तहत इसकी अनुमति नहीं थी।

8.1.11. दिल्ली का मामला वास्तव में ऐसा था जिसमें लाइसेंसधारक के खिलाफ परिसर छोड़ने और खाली करने का फरमान था। विचाराधीन डिक्री को आदेश 21 नियम 32(5) के तहत लागू करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने माना कि नियम 32(5), चीजों की प्रकृति के अनुसार, कब्ज़ा प्राप्त करने में डिक्री-धारक की सहायता नहीं कर सकता है। लेकिन अन्य उच्च न्यायालयों (ऊपर उल्लिखित) के फैसलों से निर्णय में विरोधाभास का पता चलता है।"

(14) सरूप सिंह के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों के उपर्युक्त निर्णयों पर ध्यान देने के बाद, विधि आयोग ने सिफारिशें कीं, जिसके कारण स्पष्टीकरण सम्मिलित किया गया 5। विधि आयोग की सिफारिशें पढ़ें निम्नानुसार:-

“8.1.12. सिफ़ारिश- मुद्दे पर स्पष्टता की आवश्यकता है। यह सुझाव दिया गया है कि विधायी संशोधन के मामले के रूप में, व्यापक दृष्टिकोण को शामिल करना बेहतर है (हालांकि अधिकांश उच्च न्यायालयों ने इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है) और यह प्रावधान करना कि "कार्य करने के लिए आवश्यक" शब्द निषेधात्मक (जैसा कि) को कवर करते हैं साथ ही अनिवार्य) निषेधाज्ञा। यह धारा 3(2), सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के अनुरूप भी होगा जो यह प्रावधान करता है कि सभी केंद्रीय अधिनियमों में, "अधिनियम" शब्द में अवैध चूक शामिल हैं। इसके अलावा, गुण-दोष के आधार पर, यह भी औचित्य है कि डिक्री-धारक को डिक्री के प्रवर्तन की प्रकृति में राहत पाने के लिए एक अलग मुकदमे में क्यों धकेला जाना चाहिए, जो उसे समय, श्रम और धन के काफी व्यय के बाद प्राप्त हुआ होगा।

(15) उपरोक्त ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ही सिविल जज द्वारा पारित आदेश दिनांक 23 फरवरी 2004 का परीक्षण किया जाना है। आवश्यक अभिव्यक्ति अधिनियम को निषेधात्मक के साथ-साथ अनिवार्य निषेधाज्ञा तक बढ़ा दिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को एक संकीर्ण दृष्टिकोण के रूप में माना गया है क्योंकि यह एक ऐसा मामला था, जिसमें लाइसेंसधारक के खिलाफ परिसर छोड़ने और खाली करने का आदेश था, लेकिन उच्च न्यायालय ने एक संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए अपनी असमर्थता व्यक्त की। आदेश 21

नियम 32(5) लागू करने के लिए। इसलिए, विधि आयोग द्वारा उठाए गए प्रश्न, जिसके कारण व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की गई, को उप-नियम (5) में स्पष्टीकरण जोड़कर स्वीकार कर लिया गया है। डिक्री-धारक को दूसरा मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं है जब उसने पहले ही बहुत समय और व्यय खर्च करके अपने पक्ष में डिक्री प्राप्त कर ली हो। इसलिए, न्यायालय यह निर्देश देने में पूरी तरह से सक्षम होगा कि जो कार्य किया जाना आवश्यक है वह डिक्री-धारक द्वारा स्वयं या निर्णय-देनदार की कीमत पर न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जहां तक संभव हो किया जा सकता है। अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए डिक्री के तत्काल निष्पादन में, जहां लाइसेंसधारी से कब्ज़ा मांगा जाता है। उपरोक्त आदेश कानून की भावना और विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार जोड़े गए स्पष्टीकरण के अनुरूप है। गुरुद्वारा साहिब में स्थित परिसर को खाली करने का निर्देश, जहां फैसले-देनदार याचिकाकर्ताओं को सेवादार के रूप में रहने की अनुमति दी गई थी, कब्जा सौंपने का निर्देश देने का एक और रूप और तरीका है। ट्वीडलेडी ट्वीडलम है। इसका मतलब कब्ज़ा सौंपने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है और इसलिए, विधि आयोग द्वारा सुझाए गए व्यापक दृष्टिकोण का पालन किया जाना चाहिए क्योंकि यह न्याय के उद्देश्य को पूरा करता है। तकनीकी आपत्तियां उठाकर शासनादेश को विफल नहीं किया जा सकता। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि कानून की तकनीकीताओं को न्याय को आगे बढ़ाने के लिए समझा जाना चाहिए, न कि न्याय को हराने के लिए। एलडी के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ। न्यायाधीशों, मेरा विचार है कि सरूप सिंह के मामले (सुप्रा) में दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले का अनुपात आदेश 21 के नियम 32 के उप-नियम 5 में जोड़े गए स्पष्टीकरण से काफी कम हो गया है। व्यापक दृष्टिकोण हरिहर पांडे के मामले (सुप्रा) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सही फैसला दिया है कि डिक्री धारक को एक और मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे मुकदमेबाजी बढ़ेगी जिससे सार्वजनिक नीति हतोत्साहित होगी। अदालतें उस ऋणी के अवैध मंसूबों में पक्षकार नहीं बन सकतीं जो अपना अवैध कब्ज़ा जारी रखना चाहता है। कार्ल लेवेलिन जैसे न्यायविद के नेतृत्व में यथार्थवादी विचारधारा के स्कूल द्वारा प्रचारित जमीनी हकीकत को मुकदमेबाजी और पर्याप्त पक्षकारों को समझना चाहिए।

न्याय अवश्य होना चाहिए. इसलिए, मुझे सिविल जज द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं दिखता। याचिका खारिज किये जाने योग्य है.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका

उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसमीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TraineeJudicial Officer)

कैथल, हरियाणा